



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241]	नई दिल्ली, मंगलवार, जून 26, 2018/आषाढ़ 5, 1940
No. 241]	NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 26, 2018/ASHADHA 5, 1940

## भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

### अधिसूचना

मुम्बई, 26 जून, 2018

### भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रुमेंट्स) का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता] (संशोधन) विनियम, 2018

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/26.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 17क के साथ पठित धारा 31 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 एवं 12 के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रुमेंट्स) का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रुमेंट्स) का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता] (संशोधन) विनियम, 2018 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रुमेंट्स) का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008 में,-
  - i. शीर्षक “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रुमेंट्स) का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008” निम्नलिखित शीर्षक से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) और प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट्स) का निर्गमन और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008”

ii. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,-

क. खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(खक) “आस्ति पुनर्गठन कंपनी” (असेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी) का अर्थ वही होगा, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सिक्यूरिटाइज़ेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (खक) के अधीन उसके लिए नियत है;”

ख. खंड (ज) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(ज) निवेशक (विनिधानकर्ता) से -

- (i) “प्रतिभूत ऋण लिखत” (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट) के संबंध में कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कोई प्रतिभूत ऋण लिखत [जिसके जरिए विशेष प्रयोजन वाली सुभिन्न एंटीटी (विशेष प्रयोजन की सुभिन्न सत्ता / स्पेशल पर्पस डिस्टिक्ट एंटीटी) को सौंपे गए (समनुदेशित) ऋण (डैट) या प्राप्यों (रिसीवेबल्स) में ऐसे व्यक्ति के हित (इंटरेस्ट) को अभिस्वीकृति मिलती हो] धारण (होल्ड) करता हो; और
- (ii) “प्रतिभूति रसीदों” (सिक्यूरिटी रिसीट्स) के संबंध में ऐसा अर्हित क्रेता (क्वालिफाइड बायर) अभिप्रेत है, जो प्रतिभूति रसीदें [जिनके जरिए निर्गमकर्ता (इश्युअर) को सौंपी गई (समनुदेशित) वित्तीय आस्ति (फाइनेंशियल असेट) में हित (इंटरेस्ट) को अभिस्वीकृति मिलती हो] धारण (होल्ड) करता हो;”

ग. खंड (झ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(झ) “निर्गम” (इश्यू) से -

- (i) विशेष प्रयोजन वाली सुभिन्न एंटीटी (विशेष प्रयोजन की सुभिन्न सत्ता / स्पेशल पर्पस डिस्टिक्ट एंटीटी) द्वारा या ऐसी एंटीटी की किसी स्कीम के अधीन जनता के लिए लाया जाने वाला या किसी व्यक्ति (किन्हीं व्यक्तियों) के लिए लाया जाने वाला ऐसी प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) का प्रस्ताव (ऑफर) अभिप्रेत है, जिन्हें मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो; या
- (ii) आस्ति पुनर्गठन कंपनी (असेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी) द्वारा बनाए गए न्यास (ट्रस्ट) द्वारा या ऐसे न्यास की किसी स्कीम के अधीन अर्हित क्रेताओं (क्वालिफाइड बायर्स) के लिए लाया जाने वाला ऐसी प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट्स) का प्रस्ताव (ऑफर) अभिप्रेत है, जिन्हें मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो;”

घ. खंड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(ञक) प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट्स) के संदर्भ में “निर्गमकर्ता” (इश्युअर) वह न्यास (ट्रस्ट) होगा, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों (मार्गदर्शक सिद्धांतों / गाइडलाइन्स) / विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के अनुसार आस्ति पुनर्गठन कंपनी (असेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी) द्वारा बनाया गया हो, और जिसने प्रतिभूति रसीदें निर्गमित (इश्यू) की हों या जो प्रतिभूति रसीदों को निर्गमित (इश्यू) करने का प्रस्ताव करता हो;”

ड. खंड (ठ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(ठ) “प्रस्ताव दस्तावेज” (ऑफर डॉक्यूमेंट) से कोई,-

- (i) ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है, जिसमें प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) या प्रॉस्पेक्टस के रूप में वर्णित या जारी किया गया इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज शामिल है और जिसमें कोई सूचना

(नोटिस), परिपत्र (सर्कुलर), विज्ञापन या दूसरा दस्तावेज भी शामिल है, जिसके माध्यम से जनता को पैसा लगाने (अभिदान करने / सब्सक्रिप्शन) के लिए आमंत्रित किया जाता हो या इन विनियमों के अधीन बनाई गई किसी स्कीम की किन्हीं प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) को खरीदने को कहा जाता हो; या

(ii) ऐसा दस्तावेज (जिसमें इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज शामिल है) अभिप्रेत है, जिसके माध्यम से अर्हित क्रेताओं (क्वलिफाइड बायर्स) को निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) आधार पर प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट्स) में पैसा लगाने (अभिदान करने / सब्सक्रिप्शन) के लिए आमंत्रित किया जाता हो;

च. खंड (ठ) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(ठक) प्रतिभूति रसीद (सिक्यूरिटी रिसीट) के संदर्भ में “विक्रय के लिए प्रस्ताव” (ऑफर फॉर सेल) से प्रतिभूति रसीदों के मौजूदा धारकों (होल्डर्स) द्वारा दूसरे अर्हित क्रेताओं (क्वलिफाइड बायर्स) के लिए लाया जाने वाला प्रतिभूति रसीदों का प्रस्ताव (ऑफर) अभिप्रेत है;”

छ. खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(डक) प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट) के संदर्भ में “निजी स्थानन प्रस्ताव” (प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर) से आस्ति पुनर्गठन कंपनी (असेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी) द्वारा बनाए गए न्यास (ट्रस्ट) द्वारा पैसा लगाने (अभिदान करने / सब्सक्रिप्शन) हेतु अर्हित क्रेता (क्रेताओं) के लिए लाया जाने वाला प्रतिभूति रसीदों का प्रस्ताव (ऑफर) अभिप्रेत है, और जिसमें ऐसी प्रतिभूति रसीदों के मौजूदा निवेशक (निवेशकों) द्वारा दूसरे अर्हित क्रेताओं (क्वलिफाइड बायर्स) के लिए लाया जाने वाला प्रतिभूति रसीदों का विक्रय के लिए प्रस्ताव (ऑफर फॉर सेल) शामिल है;”

ज. खंड (डक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(डख) “अर्हित क्रेता” (क्वलिफाइड बायर) का अर्थ वही होगा, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सिक्यूरिटाइज़ेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटररेस्ट एक्ट, 2002) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (प) के अधीन उसके लिए नियत है;”

झ. खंड (त) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(त) “स्कीम” से इन विनियमों के अनुसार प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) के निर्गमन (इश्यू) के लिए या वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सिक्यूरिटाइज़ेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटररेस्ट एक्ट, 2002) और/या भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों (रेग्यूलेशन्स) / दिशानिर्देशों (मार्गदर्शक सिद्धांतों / गाइडलाइन्स) के अधीन प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट्स) के निर्गमन (इश्यू) के लिए लाई जाने वाली स्कीम अभिप्रेत है और जिन्हें इन विनियमों के अधीन मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो;”

ञ. खंड (ध) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(धक) “प्रतिभूति रसीद” (सिक्यूरिटी रिसीट) का अर्थ वही होगा, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सिक्यूरिटाइज़ेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटररेस्ट एक्ट, 2002) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (यछ) में उसके लिए नियत है;”

ट. खंड (फ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

“(फ) “प्रायोजक” से -

(i) कोई वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो प्रतिभूत ऋण लिखत (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट) के निर्गमन (को जारी करने) के प्रयोजनार्थ विशेष प्रयोजन वाली सुभिन्न एंटीटी को स्थापित करता है या उसे संप्रवर्तित (प्रमोट) करता है; या

(ii) वह आस्ति पुनर्गठन कंपनी अभिप्रेत है, जिसने प्रतिभूति रसीदें निर्गमित (जारी) करने वाले किसी न्यास को स्थापित / संप्रवर्तित (प्रमोट) किया हो;”

ठ. खंड (ब) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(बक) “मूल्यांकक” से कोई वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (कंपनीज़ एक्ट, 2013) की धारा 247 के अधीन “रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक” हो;”

iii. उप-विनियम (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

“(2) इन विनियमों में अपरिभाषित, किन्तु अधिनियम या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अथवा तदधीन बनाए गए विनियमों या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर बनाए गए किन्हीं लागू नियमों अथवा विनियमों, या उनके किसी कानूनी संशोधन अथवा उनकी पुनःअधिनियमितियों में या के अधीन परिभाषित शब्दों और पदों का अर्थ वही होगा जो उन अधिनियमितियों द्वारा या के अधीन उनके लिए नियत किया गया हो, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।”

iv. विनियम 3, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

### “लागू होना

3. ये विनियम -

- (क) प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्यूरिटाइज़्ड डेट इंस्ट्रुमेंट्स) के सार्वजनिक प्रस्तावों (पब्लिक ऑफर);
  - (ख) जनता या किसी व्यक्ति (किन्हीं व्यक्तियों) को निर्गमित (जारी) की गई प्रतिभूत ऋण लिखतों की मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता (लिस्टिंग); या
  - (ग) अध्याय VIIक, अध्याय VIII तथा अध्याय X के अनुसार अर्हित क्रेता (क्रेताओं) को निर्गमित (जारी) की गई प्रतिभूति रसीदों की मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता (लिस्टिंग),
- के प्रति लागू होंगे।”

v. अध्याय VII के पश्चात् और अध्याय VIII से पूर्व, निम्नलिखित नया अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

### “अध्याय VII क

#### प्रतिभूति रसीदों का निर्गमन (इश्युएंस) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)

##### पात्रता

**38क.** प्रतिभूति रसीदों के निर्गमन (इश्युएंस) तथा इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) का या पहले से ही निर्गमित अपनी प्रतिभूति रसीदों की मात्र सूचीबद्धता का प्रस्ताव लाने वाला निर्गमकर्ता (इश्युअर) इस अध्याय के प्रावधानों (उपबंधों) का पालन करेगा।

**38ख.** जिन प्रतिभूति रसीदों को इस अध्याय के अनुसार सूचीबद्ध कराए जाने का प्रस्ताव हो, -

- i. वे प्रतिभूति रसीदें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, बनाए गए लागू नियमों और दिशानिर्देशों (मार्गदर्शक सिद्धांतों / गाइडलाइन्स) का पालन करते हुए निर्गमित (जारी) की जाएंगी;
- ii. वे प्रतिभूति रसीदें निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) आधार पर निर्गमित (जारी) की जाएंगी;
- iii. उन प्रतिभूति रसीदों के संबंध में प्रतिभूति रसीदों के निर्गमन (जारी) से संबंधित प्रावधानों का पालन किया जाएगा

#### मौजूदा धारकों (होल्डर्स) द्वारा प्रतिभूति रसीदों की बिक्री

**38ग.** (1) प्रतिभूति रसीदों का कोई मौजूदा धारक, जो प्रतिभूति रसीदों की अपनी संपूर्ण धारिता (होल्डिंग) या उसका कुछ हिस्सा, अर्हित क्रेताओं (क्वालिफाइड बायर) को निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट)

आधार पर बेचने का प्रस्ताव करता हो, जहाँ ऐसी प्रतिभूति रसीदों को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो, वहाँ वह इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार ऐसा कर सकेगा:

परंतु यह कि प्रतिभूति रसीदों के किसी धारक (होल्डर) द्वारा ऐसी बिक्री की अनुमति केवल तभी होगी, जब धारिता (होलिंग) बकाया प्रतिभूति रसीदों के पचास प्रतिशत से कम न हो।

(2) इन विनियमों के अधीन ऐसी प्रतिभूति रसीदों के किसी मौजूदा धारक द्वारा प्रतिभूति रसीदों की बिक्री, इस बात के अध्यधीन होगी कि निर्गमकर्ता (इश्युअर) इस अध्याय के प्रावधानों का पालन करने से पहले प्रतिभूति रसीदों को अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए।

### प्रतिभूति रसीदों की सूचीबद्धता के लिए शर्तें

**38घ.** (1) कोई निर्गमकर्ता (इश्युअर) अपनी प्रतिभूति रसीदों को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन सूचीबद्ध (लिस्ट) करा सकेगा:

(क) प्रतिभूति रसीदें निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) आधार पर निर्गमित (जारी) की गई हों;

(ख) निर्गमकर्ता (इश्युअर) ने ऐसी प्रतिभूति रसीदें लागू कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए निर्गमित (जारी) की हों;

(ग) प्रतिभूति रसीदों में पैसा लगाने [का अभिदान करने / को सब्सक्राइब करने] का प्रस्ताव या आमंत्रण, किसी एक वित्तीय वर्ष में, दो सौ या ऐसी दूसरी संख्या, जो समय-समय पर निर्धारित की जाए, से अधिक व्यक्तियों के लिए न लाया गया हो या को न दिया गया हो;

(घ) जिन प्रतिभूति रसीदों को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो, वे गैर-कागज़ी (डीमैट) रूप में हों;

(ङ) विनियम 38ड में बताए गए प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में कर दिए गए हों;

(च) अर्हित क्रेताओं (क्वालिफाइड बायर) को किया गया न्यूनतम आबंटन रु.10 लाख का हो;

(छ) ऐसी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन सूचीबद्धता (लिस्टिंग) से पहले करवा लिया गया हो:

परंतु यह कि ऐसा मूल्यांकन सूचीबद्धता की तारीख से तीन महीनों से अधिक पुराना न हो और जो किसी स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा किया जाए;

(ज) प्रतिभूति रसीदों की रेटिंग (साख निर्धारण) बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी द्वारा की गई हो;

परंतु यह कि ऐसी रेटिंग सूचीबद्धता (लिस्टिंग) की तारीख से तीन महीनों से अधिक पुरानी न हो।

(2) निर्गमकर्ता (इश्युअर) ऐसी प्रतिभूति रसीदों की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) संबंधी शर्तों का पालन करेगा, जैसा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2015] में निर्धारित है।

### प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट)

**38ड.** (1) जो निर्गमकर्ता (इश्युअर) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूति रसीदों को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराना चाहता हो, वह प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में ऐसे प्रकटीकरण करेगा, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएं, और जो इन विनियमों की अनुसूची Vक में निर्धारित किए गए हों:

परंतु यह कि प्रस्ताव दस्तावेज में कोई भी मिथ्या या भ्रामक कथन नहीं होगा और उसमें सभी महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट किए जाएंगे।

(2) प्रस्ताव दस्तावेज, जिसका उल्लेख उप-विनियम (1) में किया गया है, उन स्टॉक एक्सचेंजों के वेबसाइटों पर डाउनलोड करने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा, जहाँ ऐसी प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध (लिस्ट) हों।

**38च.** प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 [सिक्यूरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) रूल्स, 1957] के नियम 19 के उप-नियम (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड इन विनियमों के अनुसार निर्गमित (जारी) की गई प्रतिभूति रसीदों की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के संबंध में उक्त नियम के उप-नियम (1) से (3) को कड़ाई से लागू किए जाने के संबंध में छूट प्रदान करेगा, बशर्ते कि इन विनियमों का पालन किया जाए।

### **मूल्यांकन, रेटिंग (साख निर्धारण) तथा शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का प्रकटीकरण**

**38छ.** (1) जिस निर्गमकर्ता (इश्युअर) की प्रतिभूति रसीदें मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, वह यह सुनिश्चित करेगा कि:

- क) सूचीबद्ध (लिस्टिड) प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर (अर्थात् प्रत्येक की वर्ष 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर और 31 दिसम्बर को) कराया जाए,
- ख) मूल्यांकन स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा किया जाए; और
- ग) शुद्ध आस्ति मूल्य (नेट असेट वैल्यू) ऐसे स्वतंत्र मूल्यांकन के आधार पर निकाला जाए और उसकी घोषणा आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा तिमाही की समाप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर कर दी जाए।

(2) निर्गमकर्ता (इश्युअर) छमाही आधार पर प्रतिभूति रसीदों की क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने और उसके बाद शुद्ध आस्ति मूल्य की घोषणा करने से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक की मौजूदा अपेक्षा का भी पालन करेगा और/या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली किसी दूसरी अपेक्षा का भी पालन करेगा:

परंतु यह कि वर्ष की उन दोनों तिमाहियों में [जब बाहर से मूल्यांकन करवाना और क्रेडिट रेटिंग करवाना दोनों जरूरी हों], निर्गमकर्ता (इश्युअर) निकाले गए दोनों शुद्ध आस्ति मूल्यों में से उस शुद्ध आस्ति मूल्य को प्रकट करेगा, जो कम हो।

### **प्रतिभूति रसीदों का व्यापार (की ट्रेडिंग)**

**38ज.** (1) निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) आधार पर निर्गमित (जारी) की गई प्रतिभूति रसीदों, जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध (लिस्ट) हों, में ट्रेडिंग होगी (व्यापार होगा) और ऐसे व्यापारों (ट्रेड) का समाशोधन (क्लीयरिंग) तथा निपटान (सेटलमेंट), बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के अधीन, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में किया जाएगा।

(2) प्रतिभूति रसीदों का व्यापार लॉट (ट्रेडिंग लॉट) रु.10 लाख से कम का नहीं होगा।

(3) प्रतिभूति रसीदों में जो व्यापार (ट्रेड) बाजार से परे (ओवर द काउंटर) हुए हों, उनकी सूचना (रिपोर्ट) राष्ट्रव्यापी ट्रेडिंग (व्यापारिक) टर्मिनल वाले मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को या ऐसे अन्य प्लेटफॉर्म को दी जाएगी, जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए।

(4) बोर्ड मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या उप-विनियम (3) में उल्लिखित अन्य प्लेटफॉर्म को ट्रेड (व्यापारों) की सूचना (रिपोर्टिंग) के संबंध में शर्तें निर्धारित कर सकेगा।”

- vi. अनुसूचियों I, II, III, IV एवं V में, शीर्षक “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008” निम्नलिखित शीर्षक से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

“भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) और प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रसीट्स) का निर्गमन और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008”

- vii. अनुसूची V के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -

**“अनुसूची Vक****भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डेट इन्स्ट्रुमेंट्स) और प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट्स) का निर्गमन और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008**

(विनियम 38ड देखें)

**प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में किए जाने वाले प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र्स)**

प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में ऐसी समस्त महत्वपूर्ण जानकारी निहित होगी जो सही और पर्याप्त हो, ताकि निवेशक निर्गम (इश्यू) में निवेश करने के संबंध में सोच-समझकर निर्णय ले सकें।

प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र्स) प्रस्ताव दस्तावेज में निर्गम (इश्यू) के उद्देश्यों वाले हिस्से में प्रकट किए जाएंगे और जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

- क. निर्गमकर्ता (इश्युअर) / आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा विभिन्न बैंकों से अर्जित किए गए अनर्जक (नॉन-परफॉर्मिंग) ऋणों के ब्यौरे। इन ब्यौरों में, अन्यो के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल होंगे :
  - (i) एनपीए वर्गीकरण की तारीख;
  - (ii) आस्तियों (असेट) के ब्यौरे;
  - (iii) मंजूर की गई सीमाएं (लिमिट्स) [प्रत्येक सुविधा के अनुसार मंजूर की गई];
  - (iv) अंडरलाइंग आस्तियों (असेट्स) पर भार (चार्ज) का स्वरूप (अर्थात्, पहला भार, दूसरा भार, पूर्ण भार, आदि);
  - (v) कुल ऋण (डैट) में हिस्सा;
  - (vi) गारंटी देने वाले (वालों), यदि कोई हो (हों), के ब्यौरे;
  - (vii) मूल हक विलेखों (टाइटल डीड्स) की अभिरक्षा (कस्टडी) के ब्यौरे;
  - (viii) मुकदमे, यदि कोई हों;
  - (ix) इरादतन चूककर्ता (विलफुल डिफॉल्टर्स), यदि कोई हों;
  - (x) संपार्श्विक (कोलैटरल) का कोई मूल्यांकन, उसके पूरे ब्यौरे देते हुए;
  - (xi) संपार्श्विक (कोलैटरल) की निरीक्षण रिपोर्ट, यदि कोई हो;
  - (xii) आस्ति पुनर्गठन कंपनी की सम्यक् तत्परता संबंधी रिपोर्ट (ड्यू डिलिजन्स रिपोर्ट) में दिए गए महत्वपूर्ण निष्कर्ष;
  - (xiii) आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा बनाई गई समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान), यदि कोई हो;
- ख. अनर्जक (नॉन-परफॉर्मिंग) ऋणों में दूसरे बैंकों का कितना प्रतिशत हिस्सा है, उसके ब्यौरे।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./116/18]

**पाद टिप्पणः**

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रुमेंट्स) का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/12/126567 द्वारा, 26 मई 2008 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रुमेंट्स) का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008 तत्पश्चात्:
  - (क) 9 अप्रैल, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रुमेंट्स) का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता] (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी.-एन.आर.ओ./ओ.आई.ए.ई./जी.एन./2015-16/001, द्वारा संशोधित हुए थे।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA****NOTIFICATION**

Mumbai, the 26th June, 2018

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (PUBLIC OFFER AND LISTING OF  
SECURITISED DEBT INSTRUMENTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2018**

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/26.**—In exercise of the powers conferred by section 31 read with section 17A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) and section 30 read with sections 11 and 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) Regulations, 2008, namely:-

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) (Amendment) Regulations, 2018.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) Regulations, 2008,
  - i. the title “Securities and Exchange Board of India (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) Regulations, 2008”, shall be substituted with the following title, namely,-  
 “Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Securitised Debt Instruments and Security Receipts) Regulations, 2008”
  - ii. in regulation 2, in sub-regulation (1), -
    - a. after clause (b), the following new clause shall be inserted, namely,-  
 “(ba) “asset reconstruction company” shall have the meaning assigned to it under clause (ba) of sub-section (1) of section 2 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002;”
    - b. the clause (h) shall be substituted with the following, namely, -  
 “(h) “investor” -
      - (i) with respect to “securities debt instrument” means any person holding any securitised debt instrument which acknowledges the interest of such person in the debt or receivables assigned to the special purpose distinct entity; and
      - (ii) with respect to “security receipts” means a qualified buyer holding security receipts which acknowledges the interest in the financial asset assigned to the issuer;”
    - c. the clause (i) shall be substituted with the following, namely,-



“(i) “issue” means an –

- (i) offer of securitised debt instruments by a special purpose distinct entity or under any scheme of such entity to the public or to any person(s), which is proposed to be listed on a recognised stock exchange; or
- (ii) offer of security receipts by a trust set up by an asset reconstruction company or under any scheme of such trust to the qualified buyers, which are proposed to be listed on a recognised stock exchange;”

d. after clause (i), the following new clause shall be inserted, namely,-

“(ia) “issuer” in context of security receipts, shall be a trust set up by the asset reconstruction company in terms of guidelines/regulations as provided by the Reserve Bank of India, and have issued or proposes to issue security receipts;”

e. the clause (l) shall be substituted with the following, namely,-

“(l) “offer document” means any –

- (i) document including an electronic document described or issued as an offer document or prospectus and includes any notice, circular, advertisement or other document inviting subscription from the public or purchase of any securitised debt instruments of a scheme formulated under these regulations; or
- (ii) a document including an electronic document, inviting subscription for the security receipts from the qualified buyers on private placement basis;

f. after clause (l), the following new clause shall be inserted, namely,-

“(la) “offer for sale” in context of security receipt, shall mean an offer of security receipts by the existing holders of security receipts to other qualified buyers;”

g. after clause (m), the following new clause shall be inserted, namely,-

“(ma) “private placement offer” in context of security receipts, shall mean an offer of security receipts by a trust setup by an asset reconstruction company to a qualified buyer(s) for subscription and includes an offer for sale of security receipts by an existing investor(s) of such security receipts to other qualified buyers;

h. after clause (ma), the following clause shall be inserted, namely,-

“(mb) “qualified buyer” shall have the same meaning assigned to it in clause (u) of sub-section (1) of section 2 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002;”

i. the clause (p) shall be substituted with the following, namely,-

“(p) “scheme” means a scheme for issue of securitised debt instruments in accordance with these regulations or for issue of security receipts under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and/or regulations/guidelines as provided by the Reserve Bank of India and are proposed to be listed on a recognised stock exchange under these regulations;”

j. after clause (s), the following new clause shall be inserted, namely,-

“(sa) “security receipt” shall have the same meaning assigned to it in clause (zg) of sub-section (1) of section 2 of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002;”

k. the clause (v) shall be substituted with the following, namely,-

“(v) “sponsor” means –

- (i) any person who establishes or promotes a special purpose distinct entity for the purposes of issuance of Securitised debt instrument; or

- (ii) an asset reconstruction company who has established/promoted a trust which has issued security receipts;”
- l. after clause (w), the following new clause shall be inserted, namely,-
 

“(wa) “valuer” means any person who is a “registered valuer” under section 247 of the Companies Act, 2013;”
- iii. in regulation 2, the sub-regulation (2) shall be substituted with the following, namely, –
 

“(2) Words and expressions not defined in these Regulations, but defined in or under the Act or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or the regulations made thereunder or the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) or any applicable rules or regulations made by the Reserve Bank of India from time to time, or any statutory modification or re-enactment thereof, shall have the same meaning as have been assigned to them by or under those enactments, unless the context requires otherwise.”
- iv. in regulation 3,
  - a. in clause (a), the word “or” at the end of the sentence, shall be omitted.
  - b. in clause (b) the word “or” shall be inserted at the end of the sentence.
  - c. after clause (b), the following new clause shall be inserted, namely,-
 

“(c) to listing of security receipts issued to qualified buyer(s) on a recognized stock exchange in terms of Chapter VIIA, Chapter VIII and Chapter X.”
- v. after Chapter VII, and before Chapter VIII, the following new Chapter shall be inserted, namely, -

## “CHAPTER VII A

### ISSUANCE AND LISTING OF SECURITY RECEIPTS

#### ELIGIBILITY

**38A.** An issuer proposing to issue and list security receipts or only list its already issued security receipts shall comply with the provisions of this chapter.

**38B.** Security receipts proposed to be listed in terms of this chapter shall;

- i. be issued in compliance with the applicable rules and guidelines, as framed by the Reserve Bank of India, from time to time;
- ii. be issued on a private placement basis;
- iii. comply with the provisions pertaining to issue of security receipts,;

#### **Sale of security receipts by the existing holders**

**38C.** (1) Any existing holder of security receipts, who proposes to sell, whole or part of, its holding of security receipts to the qualified buyers on private placement basis, where such security receipts are proposed to be listed, may do so, in accordance with the provisions of this Chapter.

Provided that such sale by any holder of security receipts shall be permitted only if the holding is not less than fifty percent of the outstanding security receipts.

(2) A sale of security receipts by any existing holder of such security receipts under these regulations, shall be subject to the issuer compulsorily listing the security receipts before complying with the provisions of this chapter.

### Conditions for Listing of Security Receipts

**38D.** (1) An issuer may list its security receipts on a recognized stock exchange subject to the following conditions:

- (a) the security receipts have been issued on a private placement basis;
- (b) the issuer has issued such security receipts in compliance with the applicable laws;
- (c) the offer or invitation to subscribe to security receipts shall be made to such number of persons not exceeding two hundred or such other number, in a financial year, as may be prescribed from time to time.
- (d) the security receipts proposed to be listed are in dematerialized form;
- (e) the disclosures as provided in regulation 38E have been made in the offer document;
- (f) the minimum allotment made to the qualified buyers is Rs. 10 lakhs;
- (g) such security receipts have been valued prior to listing;  
Provided that such valuation shall not be more than three months old from the date of listing and shall be done by an independent valuer;
- (h) the security receipts have been rated by a credit rating agency registered with the Board.

Provided that such rating shall not be more than three months old from the date of listing.

(2) The issuer shall comply with the conditions of listing of such security receipts as specified in the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

### Offer Document

**38E.** (1) An issuer seeking listing of security receipts on a recognized stock exchange shall make such disclosures in the offer document as specified by the Reserve Bank of India from time to time, and as specified in Schedule VA of these regulations.

Provided that the offer document shall not contain any false or misleading statement and shall disclose all material facts.

(2) The offer document as provided in sub-regulation (1) shall be made available for download on the web sites of stock exchanges where such securities are listed.

**38F.** In exercise of the powers conferred by sub-rule (7) of rule 19 of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, the Board shall waive the strict enforcement of sub-rules (1) to (3) of the said rule in relation to listing of security receipts issued in terms of these regulations, subject to compliance with these regulations

### Valuation, rating and NAV disclosure

**38G.** (1) An issuer whose security receipts are listed on a recognized stock exchange shall ensure that:

- a) the listed security receipts are valued at the end of each quarter i.e. as on March 31, June 30, September 30 and December 31 of every year,
- b) valuation is conducted by an independent valuer; and
- c) the net asset value is calculated on the basis of such independent valuation and the same is declared by the asset reconstruction company within fifteen days of the end of the quarter.

(2) The issuer shall also comply with the extant Reserve Bank of India requirement of obtaining credit rating of security receipts at half yearly interval and declaration of the net asset value thereafter and/or any other requirement as prescribed by the Reserve Bank of India from time to time.

Provided that in those two quarters in a year, where both external valuation and credit rating are required, issuer shall disclose lower of the two calculated NAVs.

**Trading of security receipts**

**38H.** (1) The security receipts issued on a private placement basis, which are listed on recognised stock exchanges, shall be traded and such trades shall be cleared and settled in recognised stock exchanges subject to conditions specified by the Board.

(2) The trading lot of the security receipts shall not be less than Rs 10 lakh.

(3) The trades of security receipts which have been made over the counter, shall be reported on a recognized stock exchange having a nation-wide trading terminal or such other platform as may be specified by the Board.

(4) The Board may specify conditions for reporting of trades on the recognized stock exchange or other platform referred to in sub-regulation (3)."

- vi. in Schedules I, II, III, IV and V, the heading "Securities and Exchange Board of India (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) Regulations, 2008", shall be substituted with the following heading, namely.-

"Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Securitised Debt Instruments and Security Receipts) Regulations, 2008"

- vii. after Schedule V, the following Schedule shall be inserted, namely, -

**"SCHEDULE VA****Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Securitised Debt Instruments and Security Receipts) Regulations, 2008**

(See regulation 38E)

**DISCLOSURES TO BE MADE IN THE OFFER DOCUMENT**

The offer document shall contain all material information which shall be true and adequate so as to enable the investors to make informed decision on the investment in the issue.

The disclosures shall be part of the objects of the issue in the offer document and shall include:

- A. Details of non-performing loans acquired by the issuer/ asset reconstruction company from various banks. Such details shall, inter-alia, include the following:
- (i) date of NPA classification;
  - (ii) details of assets;
  - (iii) facility-wise limits sanctioned;
  - (iv) nature of charge on the underlying assets i.e. 1st charge, 2nd charge, exclusive charge etc.;
  - (v) share in total debt;
  - (vi) details of guarantor(s), if any;
  - (vii) details of custody of original title deeds;
  - (viii) litigation, if any;
  - (ix) willful defaulters, if any;
  - (x) any valuation of collateral providing full details thereof;
  - (xi) inspection report of collateral, if any;
  - (xii) material findings in the due diligence report of Asset Reconstruction Company;
  - (xiii) resolution plan formulated by Asset Reconstruction Company, if any;
- B. Details of percentage holding of non-performing loans across other banks."

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./116/18]

**Footnotes:**

1. The SEBI (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) Regulations, 2008 were published in the Gazette of India on 26th May, 2008 *vide* No. LADNRO/GN/2008/12/126567.
2. SEBI (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) Regulations, 2008 were subsequently amended on-
  - (a) April 09, 2015 by the SEBI (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) (Amendment) Regulations, 2015 published in Official Gazette *vide* Notification No. SEBI-NRO/OIAE/GN/2015-16/001.